Result Mitra Daily Magazine

कर्नाटक के 5 गारंटी योजना का वित्तीय प्रभाव

हालिया सन्दर्भ -

- कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार के पिछले एक वर्षों के मुख्य उद्देश्यों में अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना काफी अध्य रहा है।
- पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर बढ़ने से लेकर सभी संपत्तियों के गाइडेंस मूल्य को संशोधित करने तक, कर्नाटक सरकार वित्तीय हालात को सुधारने के लिए कई प्रयास कर रही है।
- दरअसल कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने 'पांच गारंटी' योजना को लागू किया है जिसका बजट लगभग 52,000 करोड़ रुपए है, जो उसके कुल बजट 3.46 लाख करोड़ रुपए का लगभग छठा भाग है।
- सरकार विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व जुटाने की गति से नाखुश है जिसे बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बोस्टन केसाल्टिंग ग्रुप (BCG) समिति का गठन किया है।
- BCG ने नए राजस्व स्रोतों की पहचान करने एवं सरकारी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण करने के सुझाव दिया था।
- प्रस्ताव में बेंगलुरु के पास 25,000 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण के उपाय भी शामिल था जिस पर विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर संपत्ति बेचने का आरोप लगाया।
- सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सरकार इस भूमि को बेचने के बजाय इसे राजस्व की निरंतर धारा प्रदान करने वाले रूप में विकसित करेगी।
- वित्त विभाग के अनुसार सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं उनसे 5500 - 6000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व सृजित होगा।

5 गारंटी -

- पिछले साल मई में सत्ता में आई कर्नाटक सरकार की वित्तीय स्थिति संदेहात्मक हो गई है।
- आलोचकों का मानना है कि राज्य सरकार की 5 गारंटी योजना राज्य को दिवालिया बना देगी।
- 5 गारंटी इस प्रकार है:-

1. शक्ति - महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा
2. गृह लक्ष्मी - परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपए
3. गृह ज्योति - प्रति परिवार 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त
4. अन्य भाग्य - परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रति महीने 5 किलो मुफ्त चावल
5. युवा निधि - स्नातकों एवं डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी भत्ता।

Result Mitra

योजनाओं का अर्थव्यवस्था पर असर -

- दिलचस्प तथ्य है कि 'शक्ति' योजना के बावजूद कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन (KSRTC) ने राजस्व में वर्ष 2023 में 17 % की बढ़ोतरी दर्ज की।
- 'शक्ति' योजना जून 2023 में शुरू की गई थी जिसके द्वारा 1 वर्ष में महिलाओं ने 250 करोड़ मुफ्त बस यात्राओं का लाभ उठाया।
- राज्य नीति संस्थान के अध्ययन के अनुसार, शक्ति योजना ने कार्य बल में महिला भागीदारी को बढ़ाया तथा GST संग्रह में वृद्धि में योगदान दिया।
- अन्य भाग्य योजना ने राज्य के कई क्षेत्रों से कुपोषण को कम किया है। हालांकि अन्य तीन योजनाओं का विश्लेषण अभी नहीं किया जा सका है।

विकासात्मक कार्यों पर ब्रेक -

- यह कोई रहस्य नहीं है लोभ लुभावना योजनाओं के लिए राज्य खजाने का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया जाता है जिससे विकासात्मक कार्यों में ठहराव आने की संभावना उत्पन्न हो जाती है।
- पिछले वर्ष 5 गारंटी योजना लागू होने के बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा था कि वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन की मांग न करें क्योंकि बजट का बड़ा हिस्सा 5 गारंटी योजना के लिए आवंटित हो गया है।

'मेरा कर, मेरा अधिकार' :-

- कर्नाटक सरकार केंद्र से अतिरिक्त राजस्व की मांग लगातार कर रहा है जिसके लिए उसने 'मेरा कर, मेरा अधिकार' अभियान चलाया है।
- कर्नाटक सरकार का कहना है कि कर्नाटक केंद्रीय खजाने में 4.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है जबकि उसे सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए ही वापस मिलते हैं।

राजस्व सृजन के उपाय -

- हाल ही में सरकार ने राजस्व सृजन करने वाले प्रमुख विभागों, जैसे वाणिज्य कर, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं उत्पाद तथा खनन क्षेत्र के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कुछ ही दिनों बाद पेट्रोल डीजल के बिक्री कर में ₹ 3 प्रति लीटर बढ़ोतरी की घोषणा की।
- सरकार को इस कदम से अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपए के राजस्व से प्राप्ति की उम्मीद है।
- राजस्व बढ़ाने के अन्य उपाय में शराब की कीमतों में संशोधन, स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी, बेंगलुरु के घरों में ठोस कचरे के संग्रहण पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव आदि शामिल है।

डीजल पेट्रोल के कीमतों का निर्धारण -

Result Mitra

- डीजल पेट्रोल को GST से बाहर रखा गया है जिसके कारण इसकी कीमत अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है।
- केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) लगाती है जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है।
- एक्साइज ड्यूटी किसी वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण पर लगाया जाता है।
- इसके अलावा राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी के अलावा VAT यानि Value added tax वसूलती है।
- राज्य सरकारें VAT की दर अपने हिसाब से तय करती है, यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों में डीजल पेट्रोल की कीमत भिन्न होती है।

Result Mitra